

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद की प्रेस वार्ता का संशोधित
प्रतिलेख: 9 अप्रैल, 2025 (बुधवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:

श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री स्वामीनाथन जे. - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. राजीव रंजन - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. ए. आर. जोशी - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संचालक:

श्री पुनीत पंचोली - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

पुनीत पंचोली:

इस वित्तीय वर्ष की पहली और इस नई व्यवस्था में आयोजित मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा; उप गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामिनाथन जे. उपस्थित हैं। हमारे साथ कार्यपालक निदेशक, डॉ. राजीव रंजन और डॉ. अजीत जोशी, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य सहकर्मी भी मौजूद हैं। महोदय, आपकी अनुमति से, हम सीधे प्रश्नोत्तर सत्र की ओर बढ़ेंगे।

संजय मल्होत्रा:

जी।

पुनीत पंचोली:

अतः, शुरू करने से पूर्व, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बारी का इंतजार करें। प्रश्न पूछने से पहले, कृपया अपने सामने लगे माइक्रोफोन को चालू करें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इस लाइव फीड को सुन रहे लोग आपको नहीं सुन पाएंगे। साथ ही, अपने प्रश्न समाप्त होने पर माइक्रोफोन बंद करने का भी कष्ट करें। समय की दृष्टि से, जैसा कि मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ, कृपया प्रति व्यक्ति केवल एक प्रश्न तक सीमित रहें और यदि समय ने अनुमति दी, तो हम दूसरा प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे। महोदय, आज मीडिया के 26 प्रतिनिधि उपस्थित हैं, और आपकी अनुमति से, हम प्रश्नोत्तर सत्र

प्रारंभ कर सकते हैं। मैं 'द हिंदू' से श्री ललतेंदु मिश्रा से अपना प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूँ।

ललतेंदु मिश्रा, द हिंदू:

पुनीत सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। गवर्नर सर, नमस्कार, और सभी को नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न उस व्यापार युद्ध के संबंध में है जिसका उल्लेख आपने पहले ही अपने वक्तव्य में किया है, जो कि चल रहे शोरगुल भरे व्यापार युद्ध के बारे में है। इसकी शुरुआत पारस्परिक शुल्क से हुई, फिर प्रतिकारी शुल्क लगा, और फिर पुनः प्रति-प्रतिकारी शुल्क लगा। मैं इसे बदले की कार्रवाई वाला शुल्क कह सकता हूँ। तो, सर, क्या हमें इससे चिंतित होना चाहिए या नहीं? और स्थिति का आपका आकलन क्या है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपने वक्तव्य में काफी हद तक दे दिया है कि इसका वैश्विक स्तर पर और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में क्या प्रभाव होने वाला है। वैश्विक स्तर पर, जैसा कि आप जानते हैं, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर के लिए अब अधिकांश पूर्वानुमान कम हो गए हैं, केवल इस वर्ष के लिए ही नहीं बल्कि अगले वर्ष के लिए भी, कम से कम 20 से 30 आधार अंक तक। और इसी तरह, मुद्रास्फीति के लिए वैश्विक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रिया है। विशेष रूप से अमेरिका के लिए, इसके द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों के कारण इसका पूर्वानुमान बढ़ने का अनुमान है। अन्य देशों के लिए, उनकी स्थिति के अनुसार प्रभाव अलग-अलग होगा। भारत के लिए, हमने अपना आकलन प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस वर्ष विकास दर को 20 आधार अंक कम किया है, जो मुख्य रूप से उन अनिश्चितताओं के कारण है, जिनके चैनलों का विस्तार से मैंने अपने वक्तव्य में वर्णन किया है। और मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, हमने कहा है कि यह दोनों दिशाओं में जा सकती है, क्योंकि अधिशेष के कारण और व्यापार शुल्क संबंधी टकराव के परिणामस्वरूप मांग में कमी आने के कारण। यह मुद्रास्फीति के मोर्चे पर सहायक हो सकता है। आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें भी कम हो गई हैं। तो, कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति की तुलना में हम विकास पर इसके प्रभाव को लेकर अधिक चिंतित हैं। और तदनुसार, आप विस्तृत जानकारी के लिए वक्तव्य पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न सीएनबीसी-टीवी18 से श्रीमती लता वेंकटेश का है।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गवर्नर महोदय, आपने एक पिछली प्रेस वार्ता में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक ब्याज दर 150 आधार अंक होनी चाहिए। अब, आपके पूर्वानुमान के अनुसार, पूरे इस वर्ष मुद्रास्फीति 4% से नीचे रहेगी, जिस स्थिति में वर्तमान वास्तविक दर वास्तव में 200 आधार अंक है। तो, क्या आपको लगता है कि दोहरी दर कटौती का अवसर है - जिसे पहले ही 50 आधार अंक की कटौती हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम उस 150 की वास्तविक दर से बहुत दूर हैं और हम 200 पर हैं? और आपका क्या मानना है कि वास्तविक दर स्वयं अगली 5 तिमाहियों में क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप मुद्रास्फीति को 4% से भी नीचे रहने की उम्मीद कर रहे हैं? आप इसका आकलन कैसे करेंगे?

और इसी से संबंधित एक प्रश्न यह है कि भूतकाल में, रिजर्व बैंक ने उस चलनिधि राशि पर मार्गदर्शन दिया था जिसने नीति संचरण में सहायता की थी। बैंकों ने कहा है कि वे चाहते हैं कि चलनिधि एनडीटीएल का 1% से 1.5% हो या ऋणात्मक 1% से 1.5% हो। क्या आप बैंकों को ऐसा कोई सुविधाजनक क्षेत्र देना चाहेंगे, जैसे कि मेरी चलनिधि सीमा 2 लाख करोड़ रुपये या जमा राशि का कुछ प्रतिशत है, ताकि संचरण सुनिश्चित हो सके?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, यह 1.5% का आंकड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने यह कहा हो; संभवतः मेरे किसी पूर्ववर्ती ने यह बयान दिया हो। हमारे पास उपलब्ध अध्ययनों के आधार पर, वास्तविक दर 1.1% से 1.9% की सीमा में होनी चाहिए। विभिन्न अध्ययन मौजूद हैं। अतः 1.5% एक काफी यथोचित वास्तविक दर या जैसा कि आप कहते हैं, 'प्राकृतिक वास्तविक दर' है।

रिपो दर के संबंध में, आगे की राह में, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'निभावकारी' कर दिया है। अतः स्पष्ट रूप से, प्रवृत्ति नीचे की ओर जाने वाली है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में, इस वर्ष औसत 4% है। अगले वर्ष का औसत क्या होगा, यह वास्तव में अभी ज्ञात नहीं है।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

क्या कैलेंडर वर्ष के लिए यह 4% से नीचे है?

संजय मल्होत्रा:

कैलेंडर वर्ष के लिए, हां, यह 4% से नीचे है, लेकिन अगली तिमाही - पहली तिमाही - के लिए यह 4% से अधिक है। हम विकसित हो रही स्थिति को देखेंगे, जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, और वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के लिए अपने पूर्वानुमान और दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये अनिश्चित समय हैं। अतः हम यह निर्णय लेंगे कि नीतिगत दर वास्तव में किस स्तर तक जानी चाहिए। चलनिधि के संबंध में, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में संख्याएं दिए बिना उल्लेख किया था कि हम इसे पर्याप्त रूप से अधिशेष में रखेंगे। मैं पुनः दोहराता हूं कि मौद्रिक नीति संचरण के उद्देश्यों के लिए हम पर्याप्त चलनिधि प्रदान करेंगे। मैं वास्तव में यह संख्या निर्दिष्ट नहीं करना चाहता कि अधिशेष कितना होना चाहिए, लेकिन यह 'पर्याप्त अधिशेष' होगा। और आपने इसे एनडीटीएल से जोड़ने का उल्लेख किया। हां, यह वही प्रकार की संख्या है, लगभग 1% या इतना ही, अधिशेष सीमा में, अब जब हम ढील के चक्र पर हैं। हम इसी प्रकार की संख्या को ध्यान में रखेंगे और इसे पर्याप्त अधिशेष में रखेंगे। वास्तविक उद्देश्य नीतिगत दर पर केंद्रित है। अतः यदि हम इसे ओवरनाइट दर तक संचारित करने में सक्षम होते हैं, तो उम्मीद है कि यह अन्य अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ब्याज दरों तक भी पहुंचेगा। जैसा कि आप जानते हैं, संचरण में थोड़ा समय लगता है। यह तत्काल नहीं होगा। हमने अतीत में देखा है कि जब हमने रिपो दर में 250 आधार अंक की वृद्धि की थी, तो नीतिगत रिपो दर में कमी के प्रतिक्रियास्वरूप ब्याज दरों में कमी होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगे थे। और वे संगत मात्रा तक कम भी नहीं हुई थीं। रिपो दर में 250 आधार अंक की वृद्धि के मुकाबले, कमी केवल लगभग 204 आधार अंक ही हुई थी। अतः हम सतर्क हैं। हम प्रणाली को पर्याप्त चलनिधि प्रदान करेंगे ताकि नीतिगत दर का ब्याज दरों में यह संचरण शीघ्रता से हो सके। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अब हम एनडीटीवी प्रॉफिट से विश्वनाथ की ओर बढ़ते हैं।

विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:

अवसर देने के लिए धन्यवाद, गवर्नर महोदय। मुझे कहना होगा कि इस कमरे में वापस आकर मुझे खुशी हो रही है। अब यह थोड़ा बेहतर दिख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता था, चूंकि आपने 'संचरण' का उल्लेख किया, तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक का यह मत था, या कम से कम रिपोर्ट्स में ऐसा सुझाव दिया गया था, कि निजी बैंकों में ऋण-जमा अनुपात अत्यधिक उच्च है और इसे कम होने की आवश्यकता है। अब जब हम संचरण की बात कर रहे हैं, तो अंततः इसका अनुवाद उच्च उधारी में होना ही होगा। क्या आप वर्तमान समय में ऋण-जमा अनुपात से संतुष्ट हैं? और दूसरा भाग यह

है कि यह धारणा है कि वर्तमान समष्टि आर्थिक ढांचे में अर्थव्यवस्था का समर्थन करने का भारी काम रिजर्व बैंक को या मौद्रिक नीति को ही करना होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में प्रबंधन के लिए आपकी जिम्मेदारी अधिक बड़ी है?

संजय मल्होत्रा:

तो, आपके पहले प्रश्न पर आते हुए, यानी ऋण-जमा अनुपात पर। देखिए, जब हम जिलों में हुआ करते थे, तो हम ऋण-जमा अनुपात को मुख्य रूप से यह देखने के लिए देखते थे कि जमा राशि के प्रतिशत के रूप में ऋण पर्याप्त है या नहीं, क्या उधारी पर्याप्त रूप से चल रही है। उस समय की बात कर रहा हूँ, लगभग 25-30 वर्ष पूर्व, हमारा मानना था कि 70-75% बहुत अच्छा है। इसलिए, कुछ क्षेत्रों में यह कम होता है क्योंकि वे बचतकर्ता होते हैं, तो कहीं अधिक उधारकर्ता होते हैं, जहां आपको उच्च ऋण-जमा अनुपात मिलता है।

आपके ऋण-जमा अनुपात संबंधी प्रश्न पर आते हुए, खैर, हमारे पास ऋण-जमा अनुपात का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आप जानते हैं कि ऋण-जमा अनुपात के लिए कोई विनियम नहीं हैं। हालांकि, हमारे पास संपत्ति-देयता प्रबंधन के लिए विनियम हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे पास चलनिधि प्रबंधन के लिए विनियम हैं, और अल्पकालिक चलनिधि के लिए विनियम हैं - एलसीआर दिशानिर्देशों के रूप में, जिनके बारे में आप जानते हैं, जो 30-दिन की अवधि के दौरान बैंकों और यहां तक कि एनबीएफसी को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और इसी तरह, दीर्घकालिक - एक वर्ष की अवधि के लिए, हमने एनएसएफआर अनुपात निर्धारित किया है।

ऋण-जमा अनुपात के संबंध में कोई अनुपात या कोई दिशानिर्देश नहीं है। बैंकों को वास्तव में अपनी संपत्ति-देयता का प्रबंधन करने के प्रति सजग रहना होगा, जो महत्वपूर्ण है। उन्हें सजग रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास अल्पकालिक चलनिधि और मध्यम एवं दीर्घकालिक दोनों के लिए पर्याप्त निधि हो, ताकि कोई बेमेल न हो और चलनिधि से संबंधित कोई समस्या न हो। अतः, वे अपनी संपत्तियों और देयताओं को देख सकते हैं और उनके अनुसार एक व्यापार योजना बना सकते हैं। हमारे पास ऋण-जमा अनुपात के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है।

आपका दूसरा प्रश्न, कि भारी काम कौन अधिक करता है, इत्यादि। यह एक संयुक्त यास है। सरकार ने अपना काम किया है, मुझे लगता है, हाल ही में आपने जो बजट देखा, उसमें बड़ी संख्या में उपाय किए गए हैं, चाहे वह बड़ी हुई पूंजीगत व्यय के संदर्भ में हो, चाहे व्यक्तिगत आयकर की ओर से कर रियायतों के संदर्भ में हो, और हमने रिपो दरों को कम

किया है। हमने आगे की राह के लिए अपना रुख बदल दिया है, जिसका अर्थ है कि नीतिगत रिपो दर की दिशा नीचे की ओर है - यह कहां तक पहुंचेगी, लता ने निश्चित रूप से वह प्रश्न पूछा, हम वास्तव में नहीं जानते। मैं संजय हूं, लेकिन मैं महाभारत का संजय नहीं हूं, जो इतना दूर तक देख सके। मेरे पास वह दिव्य दृष्टि नहीं है जो उनके पास थी, लेकिन हम संयुक्त रूप से अपने देश में वृद्धि और मुद्रास्फीति की गतिशीलता का प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अब मैं ईटी नाउ स्वदेश से अनुराग शाह को आमंत्रित करता हूं।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:

नमस्ते सर। सर, आरबीआई व्यक्तिगत ऋणों को लेकर चिंतित था, अब रुख क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि वित्त वर्ष 2025 में सबसे बड़ा खंड व्यक्तिगत ऋणों का रहा है। तो, अब जिस तरह से तकनीक व्यक्तिगत ऋणों के भीतर बदल रही है, विभिन्न खंड भी उभर रहे हैं, जिनमें हमने देखा है कि आम लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य देखभाल, बीमा प्रीमियम आदि भी व्यक्तिगत ऋण खंड के तहत आ रहे हैं, और वहां बड़ी रकम पर ब्याज भी वसूला जा रहा है। तो, क्या आज आपने जो सह-उधारी संबंधी घोषणा की है, वह उस संदर्भ में राहत दे रही है या क्या एक अलग खंड बनाया जा सकता है जहां उन लोगों को राहत दी जा सके जो आवश्यक चीजों से संबंधित ऋण लेते हैं?

और सर, एक और छोटा प्रश्न होगा। सर, आरबीआई का पहले का रुख यह था कि आपको बैंकों की सहायक कंपनियों, बीमा सहायक कंपनियों में केवल 20% तक की हिस्सेदारी की अनुमति थी। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में, हमने देखा है कि एक बैंक को 2 कंपनियों में 26% तक की अनुमति दी गई है। अब एक बैंक ने 30% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो, क्या रुख थोड़ा बदल गया है?

संजय मल्होत्रा:

आपका पहला प्रश्न यह जानने का था कि क्या हम चिंतित हैं; मैं कहना चाहूंगा कि कोई चिंता नहीं है। हमारी प्रणाली बहुत अच्छी, सुरक्षित और काफी मजबूत है। चाहे आप कुल बैंकिंग क्षेत्र की बात करें, एनबीएफसी क्षेत्र की बात करें, या व्यक्तिगत ऋणों की बात करें। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने हाल ही में व्यक्तिगत ऋणों के लिए जोखिम भार बढ़ाया था, जिसे हमने 125% कर दिया था। हमें इसे वृद्धि के रूप में नहीं देखना चाहिए। कोविड-19 से पहले जो जोखिम भार था, कोविड के दौरान हमने ऋण को और बढ़ावा देने के लिए उस जोखिम भार को कम कर दिया था। इसलिए, अब हमने उस जोखिम भार को

वापस उसी स्तर पर ला दिया है जो कोविड-पूर्व था। हमने इसे बढ़ाया नहीं है; हमने इसे मूल स्तर से ऊपर नहीं लाया है, बल्कि वापस उसी स्तर पर लाया है।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आज ऋण के जोखिम भार को कम किया जाए, जैसा कि कुछ लोग मांग रहे हैं, तो ऐसा अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए भी किया जाना चाहिए। क्योंकि हमने जो जोखिम भार बढ़ाया था, वह मूल रूप से अरक्षित व्यक्तिगत ऋणों के लिए था, जिसे वापस 125% के पुराने स्तर पर लाया गया है। तो, आप इस बात से सहमत होंगे कि एक सुरक्षित ऋण और एक असुरक्षित ऋण के जोखिम भार में कुछ अंतर होना चाहिए। इसलिए, हमने उस 25% के अंतर को वापस ला दिया है जो पहले था। अतः आज की तारीख में चिंता का कोई कारण नहीं है। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा वह यह था कि हमने कुछ बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों में निवेश का प्रतिशत बढ़ाया होगा। जहां तक मुझे ज्ञात है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। इससे पहले भी इसमें कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं था। आज की तारीख में इसके लिए कोई निश्चित प्रतिशत नहीं है, और हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आप बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, और 51% या उससे अधिक, या उससे कम यानी 30% भी निवेश कर सकते हैं। इसमें कुछ बदलावों के संदर्भ में, हमने इसके लिए मसौदा विनियम पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं। इस संदर्भ में उसमें भी कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। समग्र रूप क्या हो? यह कैसा होना चाहिए? बैंक अन्य सहायक कंपनियों और कंपनियों में कैसे निवेश कर सकते हैं? हम इसके बारे में शीघ्र ही एक उपयुक्त निर्णय लेंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्री मयूर शेटी का होगा।

मयूर शेटी, द टाइम्स ऑफ इंडिया:

धन्यवाद, सर। गवर्नर महोदय, मेरा प्रश्न स्वर्ण ऋणों और आपके द्वारा उल्लेखित विकास उपायों पर था। आपने कहा था कि नियमों का समेकन होगा, लेकिन क्या यह उन्हें और कड़ा बनाकर कसा जाएगा या उन्हें ढील दी जाएगी?

संजय मल्होत्रा:

मैंने अपने वक्तव्य में कभी 'कसाव' शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रयुक्त शब्द 'समेकन' है। बाजार इसे अपने तरीके से पढ़ रहे हैं और यह भावनाओं आदि पर आधारित है। किसी ने कहा था, मुझे लगता है कि यह बेंजामिन ग्राहम थे, जिन्होंने कहा था कि "शेयर बाजार अल्पकाल में एक वोटिंग मशीन है और दीर्घकाल में यह एक तौलने वाली मशीन है"। मुझे लगता है कि हमें दिशानिर्देशों के जारी होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे मन में कोई

कसाव नहीं है। यह केवल एक युक्तिसंगत बनाया जाना है। यह मुख्य रूप से आचरण पक्ष पर एक विस्तार है; जो दिशानिर्देश एनबीएफसी के लिए थे, उन्हें अब बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी बढ़ा दिया गया है। आप शीघ्र ही देखेंगे, हम प्रकाशित करेंगे। और ये मसौदा दिशानिर्देश हैं, जो आगे की परामर्श प्रक्रिया और फिर अंतिम रूप दिए जाने के अधीन हैं।

मयूर शेटी, द टाइम्स ऑफ इंडिया:

और तो, 1% एनडीटीएल पर स्पष्टीकरण। तो, क्या आपका मानना है कि लक्ष्य प्रणाली में 1% अधिशेष चलनिधि रखने का है, जो लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये है?

संजय मल्होत्रा:

मैं खुद को ठीक 1% तक सीमित नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हां, यह उसी प्रकार की सीमा है, उस सीमा के आसपास। यदि अधिक की आवश्यकता होगी, तो हम अधिक करेंगे। यदि कम की आवश्यकता होगी, तो हम कम करेंगे। मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, रिपो दर का ब्याज दरों में उचित संचरण सुनिश्चित करना है।

मयूर शेटी, द टाइम्स ऑफ इंडिया:

धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

क्या आप स्वर्ण ऋण दिशानिर्देशों पर कुछ और जोड़ना चाहेंगे या हम प्रकाशन की प्रतीक्षा करें?

एम. राजेश्वर राव:

नहीं, मुझे लगता है कि आपने इसे कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि मसौदा परिपत्र शीघ्र ही सार्वजनिक डोमेन में आ जाएगा और आप वहां विवरण देख सकते हैं।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। अगला प्रश्न बिजनेस स्टैंडर्ड से श्री मनोजित साहा का है।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

शुभ अपराह्न। धन्यवाद। आपने एक दिलचस्प बात कही कि नीतिगत रुख का सीधा आकलन नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि रिजर्व बैंक ने पहले भी यह कहा था, लेकिन इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं, कि नीतिगत रुख का सीधा संबंध चलनिधि की स्थितियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि मैंने सही समझा है, तो आपका लक्ष्य एनडीटीएल का

लगभग 1% अधिशेष चलनिधि बनाए रखना है। तो, आपका इससे क्या अभिप्राय है? मुझे ज्ञात है कि चलनिधि ढांचे में संशोधन किया गया है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? संशोधित चलनिधि ढांचे के बारे में क्या विचार हैं?

संजय मल्होत्रा:

इसकी प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, वर्तमान में चलनिधि ढांचे के तहत, हम मुख्य रूप से मुद्रा बाजार में एकदिवसीय दर को देख रहे हैं। और इसलिए, यह देखना कि क्या नीतिगत रेपो दर के संचरण के उद्देश्यों के लिए इसे वही बनाए रखना चाहिए, या क्या हमें केवल यही लक्ष्य बनाना चाहिए या किसी अन्य चीज को लक्ष्य बनाना चाहिए। यह वह विषय है जिस पर हम विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर रहे हैं और शीघ्र ही हम इसके साथ सामने आएंगे। हमारे पास वास्तव में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं है क्योंकि इस मामले पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है। उप गवर्नर रबी शंकर, क्या आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे?

टी. रबी शंकर:

नहीं। मुझे लगता है कि एक बार जब हम इसे अंतिम रूप दे देंगे। जैसा कि गवर्नर ने कहा, हम वर्तमान में मुद्रों पर चर्चा कर रहे हैं। और इनमें से एक बात यह है कि लक्ष्य दर क्या होनी चाहिए, यह देखते हुए कि अन्य रात भर के वॉल्यूम की तुलना में कॉल वॉल्यूम काफी कम हो गए हैं। और किसी भी ढांचे के संशोधन, पुनर्विचार या समीक्षा के लिए हमेशा की तरह, हम उन सभी उपकरणों को देखेंगे जिनका हम उपयोग करते हैं। वर्तमान में, हम विभिन्न परिपक्वता, चर, स्थिर और अन्य प्रकार के उपकरणों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं। हम उन दरों को देखेंगे और यह देखेंगे कि क्या बदलाव की आवश्यकता है।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

उद्देश्य संचरण को तेज करना भी है। संचरण में अब दो तिमाहियां लगती हैं। क्या उद्देश्य संचरण को तेज करना भी है? क्या आप उम्मीद करते हैं कि बैंक इस 50 आधार अंक की कटौती को जल्दी लागू करें? इस पर आपके क्या विचार हैं?

संजय मल्होत्रा:

हाँ, जाहिर है कि कोई भी चाहेगा कि संचरण यथासंभव शीघ्र हो, लेकिन फिर भी यह विघटनकारी नहीं होना चाहिए। तो, हम यह कैसे करें? यह फिर से एक ऐसा विषय है जिस पर हम विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

कब, सर?

संजय मल्होत्रा:

शीघ्र ही। मैं कोई तारीख नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी टीम के साथ इसकी समीक्षा नहीं की है। लेकिन हम इसे यथासंभव शीघ्र करने की उम्मीद कर रहे हैं।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास रॉयटर्स से सुश्री स्वाति होंगी।

स्वाति भट, थॉमसन रॉयटर्स:

बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि शुल्क प्रमुख विषय रहे हैं और इस पर काफी चर्चा हुई है, इसलिए मैं केवल यह समझना चाहती थी कि चीन संभावित रूप से शुल्क युद्ध में अमेरिका को जवाब देने के लिए युआन के अवमूल्यन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करेगा। हमने अप्रैल में भारत से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बहिर्वाह भी देखे हैं। हम देख सकते हैं कि अधिशेष का शेष ऋणात्मक हो सकता है। रिजर्व बैंक की मुद्रा प्रबंधन रणनीति क्या होगी? क्योंकि रुपये पर निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा जो आगे चलकर युआन के साथ होता है और उसी तरह, जब हमने जीएफसी, कोविड आदि जैसी पिछली संकट की अवधियों को देखा है, तो हमने वैश्विक केंद्रीय बैंकों के बीच काफी अधिक सहयोग और समन्वय देखा है। क्या ऐसा कुछ अभी भी हो रहा है? क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

मेरी समझ यह है कि, देखिए, इन शुल्कों का भारत पर प्रभाव, कुछ अन्य देशों—जिनका आपने उल्लेख किया, चीन और कुछ छोटे देशों—की तुलना में कहीं कम है। हमारे निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12% हैं, जबकि अमेरिका के लिए यह 1% से भी कम या 2% है, और आप इसकी तुलना कुछ अन्य देशों, यहां तक कि चीन से भी करें। चीन का निर्यात लगभग 19% है, जर्मनी का 37% है और यहां तक कि यूरोपीय संघ का भी 30% से अधिक है, जबकि छोटे देशों का लगभग 80% है। मैं उन देशों—वियतनाम, ताइवान आदि—की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए, उस हद तक हम कुछ अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत पर लगाए गए ये पारस्परिक शुल्क कुछ अन्य देशों की तुलना में कम हैं, क्योंकि उन देशों के मुकाबले हमारा अधिशेष बहुत कम है। और इसलिए, कुछ मायनों में, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी उल्लेख किया है कि हमारे पास तुलनात्मक लाभ है। अमेरिका के संबंध में आपका कुछ इन देशों

की तुलना में तुलनात्मक लाभ हो सकता है। लेकिन समग्र रूप से, निश्चित रूप से, यह अभी भी वृद्धि के लिए एक अवरोधक है। और जहां तक मुद्रा प्रबंधन का प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं, हम वास्तव में मुद्रा प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम केवल अत्यधिक या विघटनकारी अस्थिरता के लिए ही ऐसा करते हैं। हम भारतीय रुपये के किसी भी स्तर, सीमा या रेंज को प्रबंधित या लक्षित करने का प्रयास नहीं करते हैं।

स्वाति भट, थॉमसन रॉयटर्स:

बस इसे स्पष्ट करते हुए। तो, क्या यह कहना उचित होगा कि यदि रुपये पर अवमूल्यन का दबाव है, तो आरबीआई इसे गिरने देगा, या यह कहना उचित होगा कि यदि वैश्विक मुद्राएं गिर रही हैं, उभरते बाजारों की मुद्राएं गिर रही हैं...?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यदि अत्यधिक (अस्थिरता) होती है... हम किसी स्तर को लक्षित नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि भारत के बाजार काफी गहरे और व्यापक हैं, और बाजार शक्तियां सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि स्तर क्या होने चाहिए। यह कहते हुए भी, यदि किसी अत्यधिक अस्थिरता के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो हम कमी महसूस नहीं होने देंगे। जहां भी आवश्यकता होगी, हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि केवल एक प्रश्न पूछें ताकि सभी को पूछने का अवसर मिल सके। तो, अगला, मैं पीटीआई से श्री आशीष से यह प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। आपने उल्लेख किया कि आप दरों के भविष्य के मार्ग की संभावना नहीं बता सकते। लेकिन सर, यदि प्रमुख केंद्रीय बैंक लंबे समय तक अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, तो रुख क्या होगा? आपने रुख में बदलाव किया है, लेकिन क्या यह हमें आगे कटौती करने के लिए जगह देगा?

संजय मल्होत्रा:

मैंने अपनी मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया है कि इन वैश्विक शुल्कों, आदि और अनिश्चितताओं का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव हो सकता है, और भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और मुख्य रूप से, हमारा मानना है कि घरेलू मुद्रास्फीति और विकास ही

हमारे रुख और हमारी नीतिगत रेपो दरों को संचालित और निर्धारित करेंगे। इसलिए, हम अपने घरेलू पहलुओं को देखते रहेंगे... हालांकि सतर्क रहेंगे, बेशक, और उनका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हम बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि हमारा आयात-निर्यात, बाहर की दुनिया के साथ हमारा आपसी जुड़ाव कुछ छोटी अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं कम है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगल, हमारे पास ब्लूमबर्ग से श्री अनुप होंगे।

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:

गवर्नर महोदय, शुल्क लागू हो चुके हैं। क्या आप क्षेत्र में एक मुद्रा युद्ध की उम्मीद करते हैं, यह देखते हुए कि यहां विभिन्न दरों पर शुल्क लग रहे हैं, और आप ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

संजय मल्होत्रा:

मुझे समझ नहीं आया, आप 'मुद्रा युद्ध' से क्या मतलब ले रहे हैं?

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:

मुद्रा की प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन, सर।

संजय मल्होत्रा:

मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या होगा। मुद्राओं के मामले में, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हमारी मुद्रा काफी स्थिर है, हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं, जो अब लगभग 700 अरब अमेरिकी डलर है और बढ़ रहा है, और हमारे घाटे भी, दोनों इस वर्ष और आगामी वर्ष के लिए - 1%, बहुत ही स्थायी हैं। इसलिए, मुझे वास्तव में नहीं लगता कि हम किसी तरह के तनावपूर्ण स्थिति में हैं। फिर से, मैंने उल्लेख किया और मुझे लगता है कि यह यहां प्रासंगिक है कि हमारा आपसी जुड़ाव, विशेष रूप से व्यापार के मामले में, कम है। पूंजी प्रवाह के लिए फिर से, हमें यहां अच्छे विकास की आवश्यकता है। वह मदद करेगा और हम स्थिति के विकसित होने के साथ देखेंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। आगे बढ़ते हुए, हमारे पास ईटी नाउ से अंकुर होंगे।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गवर्नर महोदय, हमने अतीत में देखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक सह-उधार व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा चिंतित रहा है और कुछ जांच भी हुई हैं। आज आपने घोषणा की है कि बैंकों और एनबीएफसी के बीच की व्यवस्था को सभी अन्य विनियमित इकाइयों तक बढ़ाया जाएगा और पहले प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पहली वरीयता थी। अब आप कह रहे हैं कि अन्य सभी ऋणों का भी उपयोग किया जा सकता है। क्या इन मानदंडों पर, दोनों प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर - क्योंकि मैंने देखा कि पहले पीएसएल मानदंडों में निर्धारित सीमा बढ़ाई गई थी - और अब बैंकों और अन्य इकाइयों के बीच इस सह-उधार व्यवस्था पर, भारतीय रिजर्व बैंक के रुख में कोई बदलाव आया है?

संजय मल्होत्रा:

मुझे वह बदलाव समझ नहीं आ रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। यदि कोई बदलाव है, तो मैं उप गवर्नर से आने का अनुरोध करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि सह-उधार व्यवस्था ने वास्तव में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में मदद की है क्योंकि यह केवल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तक सीमित थी। और अब हम जो कर रहे हैं, उसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से बाहर के अन्य खंडों तक भी विस्तारित कर रहे हैं। इसके अलावा, हम इसे विस्तारित कर रहे हैं; अभी तक केवल विनियमित इकाइयां, केवल बैंक और एनबीएफसी ही इस व्यवस्था में प्रवेश कर सकते थे। अब दो बैंक भी एक साथ इस व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। हम जो मूल लाभ देखते हैं वह यह है कि एक ओर, उधारकर्ताओं को लाभ मिलता है, आपको ब्याज दरों में कमी का लाभ मिलता है क्योंकि बैंकों के पास कम दरों पर धनराशि होती है और जो उनकी पहुंच में नहीं है, उसे एनबीएफसी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए, यह मुख्य रूप से बैंकों और एनबीएफसी के लिए एक विजयी स्थिति है। इसलिए, हम इसे विस्तारित कर रहे हैं। क्या आप सह-उधार पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्या हमारे रुख में कोई बदलाव आया है?

स्वामिनाथन जे.:

बहुत ज्यादा नहीं, सर। मुझे नहीं लगता कि रुख (stance) में कोई बदलाव आया है। मूल रूप से, जैसा कि आपने कहा, हम प्रतिभागियों का विस्तार कर रहे हैं इसे सभी विनियमित संस्थाओं तक बढ़ाकर। और हम कवरेज को पीएसएल से परे भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक सामंजस्य भी ला रहे हैं ताकि जब अधिक खिलाड़ी आएँ और अधिक खंड खुलें, तो अधिक स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए। इसलिए, दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे, और हम फिर से फीडबैक लेंगे और यदि इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता होगी, तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन यह बाजार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था रही है। हालांकि प्रबंधन के तहत संपत्ति अभी तक महत्वपूर्ण नहीं है, संभवतः प्रतिभागियों और

खंडों का व्यापक आधार करके, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें तेजी आएगी। इसलिए, दिशा-निर्देश अधिक सुविधाजनक होंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधारकर्ता को अंततः उस व्यक्ति का लाभ मिले जिसके पास लागत का लाभ है और उस व्यक्ति का लाभ जिसके पास पहुंच है। दोनों का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अब मैं जी बिज़नेस से एकता सूरी को उनका प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करूंगा।

एकता सूरी, जी बिज़नेस:

शुभ अपराह्न, सर। सर, हाल ही में आपने कुछ अवसरों पर कहा है कि ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए, उन्हें बार-बार फोन कॉल नहीं आने चाहिए। तो, हमें इस संबंध में क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि सीकेवाईसी में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत दोहराव है, और डेटा पुराना है। दूसरी बात, यदि बैंकों पर भरोसा किया जाना है, तो बहुत सारे डिजिटल धोखाधड़ी के मामले हैं, लेकिन अब भी यदि ग्राहक अपने वास्तविक धोखाधड़ी के मामलों के साथ बैंकों के पास जाते हैं, तो भी उन्हें अपना पैसा वापस पाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या वहां कोई सख्त रुख अपनाया जाएगा? क्या 'म्यूल हंटर'(फर्जी/ठगी खाते का पता लगाने वाला, इसमें मदद कर रहा है, या बैंक एपीआई को आईसी 4 के साथ एकीकृत किया जा रहा है? क्या उस प्रक्रिया को तेज करने का कोई प्रयास है? हम क्या देख सकते हैं कि बैंकिंग में ग्राहकों के लिए केवाईसी को आसान बनाया जाए और यह अधिक विश्वसनीय हो, ताकि उनका विश्वास वापस जीता जा सके?

संजय मल्होत्रा:

हमारे लिए केवाईसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, कि हम इसे कैसे 'सरल, सुगम, सस्ता' बना सकते हैं। इसके लिए हमें बैंकों और सीईआरएसएआई, जो सीकेवाईसीआर बनाए रखता है, के साथ काम करना होगा। हमें उनके साथ अपने समन्वय को बेहतर बनाने के तरीके पर काम करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में विनियमित संस्थाएं हैं जो विभिन्न स्थानों पर केवाईसी कर रही हैं। तो, इसे एक एकीकृत डेटाबेस कैसे बनाया जा सकता है जिसमें किसी भी विनियामक या किसी भी आयोग के तहत किसी भी विनियमित इकाई द्वारा किसी व्यक्ति की केवाईसी की गई हो, और यदि केवाईसी हो गई है तो उन्हें अन्य विनियामक संस्थाओं में फिर से केवाईसी कराने की आवश्यकता न हो। सीईआरएसएआई, सीकेवाईसीआर को उन्नत बनाने के लिए काम

कर रहा है और सीकेवाईसीआर 2.0 की दिशा में कदम उठाए हैं, और उनके पास लगभग 100 करोड़ रिकॉर्ड हैं। उन्होंने पहले ही काफी बड़ी संख्या में यह काम कर लिया है जिसका हम भविष्य में लाभ उठा सकते हैं। गुणवत्ता के मुद्दे, जैसा कि आपने उल्लेख किया, हमें उसे सुधारना होगा। भारत सरकार ने निर्देश दिया है और उन्होंने एक नियम बनाया है, और हमने भी सभी विनियमित इकाइयों को निर्देशित किया है कि इसका पालन किया जाना चाहिए; केवाईसी करने से पहले उन्हें सीकेवाईसी की जांच करनी होगी, यदि दस्तावेज पहले से ही सीकेवाईसी में उपलब्ध हैं, यदि केवाईसी पहले से ही हो चुकी है, तो उन्हें दोबारा केवाईसी दस्तावेज नहीं लेने चाहिए। नियमों और निर्देशों का पालन करने में समय लगता है क्योंकि बैंकों को अपने आईटी सिस्टम में बदलाव करने की आवश्यकता है। परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि यह हमारी प्राथमिकता है और भारत सरकार की भी प्राथमिकता है, इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में केवाईसी आसान, सरल और सस्ती होगी। धोखाधड़ी के मुद्दे पर, हमने कई कदम उठाए हैं। मैं उप गवर्नर स्वामीनाथन से अनुरोध करूंगा कि वे विस्तार से बताएं कि धोखाधड़ी के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं और 'म्यूल हंटर'(फर्जी/ठगी खाते का पता लगाने वाला) के संबंध में कि हम अगले एक वर्ष में कहां पहुंचना चाहते हैं और आज हम कहां हैं। तो, आपने एक साथ बहुत से प्रश्न पूछे हैं।

स्वामिनाथन जे.:

प्रतिक्रियाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, मूल रूप से डिजिटल धोखाधड़ी हम सभी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रही है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि बैंक स्तर पर संचालित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और अग्र-सक्रिय जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार किया जाए ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। हाँ, बेशक, आपने यह भी उल्लेख किया कि यदि यह घटित होती है तो मुआवजा क्या होना चाहिए? देयता सीमित करने वाले दिशा-निर्देश पहले से ही लागू हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसा धन बहुत तेजी से चलता है और अक्सर यह विनियमित संस्थाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। लेकिन जहाँ भी संभव हो, इसे जब्त किया जा रहा है और वापस किया जा रहा है, जबकि सफलता दर इस बात पर निर्भर करती है कि शिकायत कितनी जल्दी दर्ज की जाती है और उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है।

आपने आई4सी (I4सी) एकीकरण का भी उल्लेख किया। आज, सभी बैंक आई4सी प्रणाली के साथ बहुत सक्रिय और पूर्वग्रह रूप से एकीकृत हैं, और सभी बैंकों को 24x7 हेल्पलाइन और समर्पित अधिकारी रखने का भी अनिवार्य किया गया है जो इन कॉलों को संभालेंगे ताकि किसी भी समय बहुत जल्दी कार्रवाई की जा सके। चिकित्सा प्रणाली में जिस सुनहरे

समय 'गोल्डन आवर' में विश्वास किया जाता है, हमें डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में भी वही अपनाना चाहिए।

तीसरा, फर्जी/ठगी खाते का पता लगाने वाला 'म्यूल हंटर' के संदर्भ में, प्रायोगिक परियोजनाएं अत्यंत सफल रही हैं। पूरे सिस्टम स्तर के डेटा को प्राप्त करने के संदर्भ में जो परिणाम सामने आ रहे हैं, वे यह दर्शाते हैं कि बैंकों में धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली अपने स्वयं के बैंक डेटा पर काम करती है, जबकि फर्जी/ठगी खाते का पता लगाने वाला 'म्यूल हंटर' सिस्टम स्तर के डेटा को सुविधाजनक बनाता है। बड़े बैंकों के साथ हमने जो पायलट किए हैं, वे अत्यंत सफल रहे हैं। परिणाम लगभग वास्तविक समय के करीब हैं और मॉडल प्रभावी साबित हुए हैं। लेकिन ये एआई/एमएल आधारित मॉडल हैं, इन्हें सीखने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इन्हें और अधिक सफल होने के लिए अधिक डेटा को पचाने की आवश्यकता है। इसलिए, हम इस पायलट को यथाशीघ्र उत्पादन में ले जाएंगे। इन्नोवेशन हब इस पर काम कर रहा है। अधिकांश बड़े बैंक इसमें भाग ले रहे हैं। हमारा इरादा यह है कि हम यथासंभव वास्तविक समय के करीब पहुंचें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी को यथासंभव रोका जाए और यदि धोखाधड़ी घटित होती है तो यथासंभव और यथाशीघ्र राशि वसूल की जाए। यही लक्ष्य है। लेकिन यह एक यात्रा होगी क्योंकि हमें यह याद रखना होगा कि धोखाधड़ी करने वाले हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। इसलिए, हम अनिवार्य रूप से एक बराबरी कर लेने वाले खेल में हैं, लेकिन हम शायद बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। अगला, हमारे पास द मिंट से गोपिका होंगी।

गोपिका गोपाकुमार, द मिंट:

धन्यवाद, सर। नमस्ते गवर्नर महोदय। जब से आपने पदभार संभाला है, हमने तीन अलग-अलग संस्थाओं में तीन संकट देखे हैं। एक निजी क्षेत्र के बैंक में, एक नए सहकारी बैंक में और एक आवास वित्त कंपनी में। ये तीनों संकट लंबे समय तक आरबीआई की नाक के नीचे हुए? इससे आरबीआई की क्या सीख है? और दूसरी बात, निजी क्षेत्र के बैंक, इंडसइंड बैंक विशिष्ट रूप से, आरबीआई को आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई होगी। क्या कोई ऐसी चिंताएं हैं जिनके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए? और प्रबंधन को जारी रहने की अनुमति दी गई है। तो, क्या आप इस पर अपने विचार बता सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

व्यक्तिगत संस्थाओं के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, हम व्यक्तिगत संस्थाओं के विवरण में नहीं जाते। प्रणाली स्तर पर, मैं कहूंगा कि, और मैंने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है, चाहे वह सहकारी बैंक हों, चाहे एनबीएफसी हों या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आदि, सिस्टम स्तर पर हम बहुत सुरक्षित, महफूज़ और मजबूत हैं। प्रणाली लचीली है। दूसरी बात यह है कि इसे ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक बहुत, बहुत बड़ी प्रणाली है। खिलाड़ियों की बड़ी संख्या है, लगभग 10,000 एनबीएफसी हैं। लगभग 1,500 सहकारी बैंक हैं। मैं पिछले आठ या नौ वर्षों के डेटा को देख रहा था, 1,500 सहकारी बैंकों में से कुछ 70 सहकारी बैंक... तो, यह लगभग बनाता है, आप गणना कर सकते हैं। तो, यह संख्या में बहुत छोटा है। यदि आप इसे देखें, तो मेरे पास उसका समर्थन करने के लिए डेटा नहीं होगा, लेकिन मैं मानने को प्रवृत्त हूँ, और मैं इन्हें पूर्ण विफलताएं भी नहीं कहूंगा। ये प्रकरण हैं, है ना? ये विफलताएं भी नहीं हैं। ये प्रकरण घटित होते रहेंगे। हमारा प्रयास विभिन्न साधनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि ये घटनाएं, घटनाएं कम आवृत्ति में हों। वे कम आवृत्ति में घटित हों। और इसके लिए, हमारे पास विभिन्न उपकरण हैं। हमारे पास विनियम हैं। हमारे पास हमारी पर्यवेक्षण है। बैंकों के पास स्वयं कई परतें होती हैं। उनके पास तीन परतें होती हैं, व्यवसाय इकाई परत, उनका अनुपालन परत, और फिर उनका ऑडिट। तो, हम सभी को एक साथ काम करना होगा और लगातार प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करना होगा।

संगीता मेहता, द इकोनॉमिक टाइम्स:

धन्यवाद, सर। सर, गोपिका के प्रश्न से संबंधित, इंडसइंड के संदर्भ में, क्या आरबीआई लेखापरीक्षकों पर कोई कार्रवाई कर सकता है? मेरा मतलब है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि यह पांच से सात वर्षों से हो रहा है। लेखापरीक्षक इसे पूरी तरह से कैसे चूक गए?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि मैंने उल्लेख किया, मैं किसी व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत लेखापरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के विवरण में नहीं जाना चाहूंगा। हमारे पास अच्छी प्रणालियां स्थापित हैं ताकि जहां तक संभव हो, यथाशीघ्र पता लगाया जा सके। गैर-अनुपालन, जोखिमों का पता लगाने के बाद हम यथासंभव पूर्व-निवारक और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं।

स्वामीनाथन जे.:

गवर्नर द्वारा दोनों प्रश्नों के संदर्भ में कही गई बातों का पूरक करने के लिए, किसी विशेष इकाई में गए बिना, एक बात तो यह है कि हम निश्चित रूप से कभी भी एक अच्छे संकट

को बर्बाद नहीं करते। इससे सीख मिलेगी। और जैसे-जैसे ये प्रकरण सामने आएंगे, पर्यवेक्षणीय उपकरण बेहतर होते जाएंगे। हमारा इरादा न्यूनतम करने का है और, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक सुरक्षित रहें, भले ही दुर्घटनाएं घटित हों। इसलिए, इनमें से प्रत्येक संकट में, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि ग्राहक की असुविधा को कम से कम किया जाए और ग्राहक के धन को यथासंभव सुरक्षित रखा जाए ताकि इन प्रकरणों का स्वतंत्र रूप से निपटारा किया जा सके। आपके प्रश्न पर आते हुए, मूल रूप से जब भी ऐसी विफलताएं होती हैं, तो यह इसका हिस्सा है जबकि निश्चित रूप से हम ग्राहकों की सुरक्षा के संदर्भ में जोखिम दूर करने के उपाय करते हैं। दूसरी ओर, हम बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी देते हैं कि उचित फॉरेंसिक और जवाबदेही अध्ययन किए जाएं और फिर चाहे वे आंतरिक हों, बाहरी हों या सेवा प्रदाता हों, जो कोई भी जिम्मेदार है, उन सभी को उसमें शामिल किया जाएगा और कार्रवाई होगी और यह अपने उचित मार्ग पर चलेगी यदि कोई चूक हुई तो उनका उचित निपटारा किया जाएगा। मैं किसी विशेष प्रकरण के विशिष्ट संदर्भ में नहीं कहना चाहता, लेकिन हर प्रकरण में, की गई मरम्मत के अलावा, एक जवाबदेही भी होगी जो आएगी। हम उस परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। हमें यहां इसके बारे में अटकलें लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह...

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:

आपने फॉरेंसिक और एक और रिपोर्ट का उल्लेख किया... एक जवाबदेही रिपोर्ट?

स्वामीनाथन जे.:

जवाबदेही रिपोर्ट, यह उसका एक हिस्सा है। यह मूल रूप से यह देखने के लिए हो सकता है कि क्या कोई चूक हुई थी, और यदि चूक हुई है, तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह हर ऐसे प्रकरण का हिस्सा है जो सामने आता है। हम मूल रूप से यह सुनिश्चित करने को लेकर अधिक चिंतित हैं कि सुधार यथाशीघ्र किया जाए और ग्राहकों को कोई हानि या असुविधा न हो। ये मूल रूप से हमारी प्राथमिकताएं हैं। यह वह चीज है जिससे हम प्राथमिकता के आधार पर निपटते हैं। फिर उन लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं जिनपर जवाबदेही निश्चित हुई है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। सर, आपकी अनुमति से, अंतिम चार प्रश्न।

संजय मल्होत्रा:

हां।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। हमारे पास द हिंदू बिजनेस लाइन से श्री पीयूष होंगे।

पीयूष शुक्ला, द हिंदू बिजनेस लाइन:

नमस्कार, गवर्नर महोदय, उप गवर्नर महोदय, धन्यवाद पुनीत सर। सर, स्वर्ण ऋणों के संदर्भ में, मूल रूप से एनबीएफसी का ऋण-मूल्य अनुपात लगभग 70% से 80% के बीच होता है और बैंकों का लगभग 60% से 70% के बीच होता है। तो, जब आप कहते हैं कि आप मानदंडों का सामंजस्य करेंगे, तो क्या आप उसे एक सामान्य स्तर पर लाएंगे? अलग से, सर, आपने बैंकों की अपेक्षाकृत कम संख्या में विफलताओं के बारे में बात की। एनआईसीबी के संदर्भ में, आपने कुछ छूट भी दी है। लेकिन क्या आपने इसका आकलन किया है कि वास्तव में कितनी धोखेधड़ी हुई, राशि कितनी थी? और क्या आप वास्तव में बैंक को फिर से ग्राहकों को स्वीकार करने देंगे? मेरा मतलब है, क्या आप प्रतिबंध हटा देंगे, या प्रभाव इतना गंभीर है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे? धन्यवाद। बस एक स्पष्टीकरण, निभावकारी रुख क्या यह सर्वसम्मत था या वहां कोई...?

संजय मल्होत्रा:

मैंने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया था कि यह सर्वसम्मत है।

स्वाति भट, रॉयटर्स:

वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं था।

संजय मल्होत्रा:

तो, यह निश्चित रूप से सर्वसम्मत था। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत रूप से निर्णय लिया। उस पर कोई मतदान नहीं हुआ, लेकिन उन सभी ने सर्वसम्मत रूप से यह निर्णय लिया कि वे महसूस करते हैं कि आगे की राह वास्तव में ठील देने की राह है। ऋण-मूल्य अनुपात के संबंध में, आपको शीघ्र ही दिशा-निर्देश मिल जाएंगे। हम अटकलें न लगाएं। स्वर्ण ऋणों के संबंध में आपको शीघ्र ही दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे। आपका दूसरा प्रश्न क्या था?

पीयूष शुक्ला, द हिंदू बिजनेस लाइन:

एनआईसीबी सर, क्या आप उन्हें हटा देंगे?

संजय मल्होत्रा:

हम विशिष्ट इकाइयों संस्थाओं के विवरण में नहीं जाते। हमारा प्रयास, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उपभोक्ताओं और ग्राहकों की रक्षा करना, उनके हितों की सुरक्षा करना है। और आगे बढ़ते हुए, देखना है कि हम स्थिति को बचाने और सुधारने के लिए सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं। सभी इकाइयों के लिए यही हमारा प्रयास है। और इस मामले में भी वैसा ही होगा।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। और अब दाईं ओर से इंफॉर्मिस्ट मीडिया से श्री सिद्धार्थ।

सिद्धार्थ उपासनी, इंफॉर्मिस्ट मीडिया:

धन्यवाद, सर। शुभ अपराह्न गवर्नर महोदय। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपनी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद की परियोजनाओं के लिए 86 रुपये प्रति डॉलर की विनिमय दर मानी है और यह भी कहा है कि कोई प्रमुख संरचनात्मक नीतिगत बदलाव नहीं होंगे। क्या हम इससे यह अनुमान लगाएं कि आरबीआई को चल रहे टैरिफ युद्ध से रुपये पर बहुत कम दबाव की उम्मीद है, और भारत और अमेरिका इस वर्ष किसी भी प्रकार का समझौता करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं? दूसरा, चलनिधि पर, जब प्रणाली में इतनी अधिक अधिशेष चलनिधि - लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक - मौजूद है, तो आरबीआई अभी भी परिवर्ती दर रेपो(वीआरआर) क्यों कर रहा है? क्या कोई निर्धारित सीमा है? क्या इसे नियंत्रित करने वाला कोई ढांचा है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मानना है कि वितरण विषम है और बैंकों द्वारा चलनिधि को बनाए रखने की वरीयता बढ़ गई है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

सबसे पहले आपका दूसरा प्रश्न, चलनिधि, वास्तव में वीआरआर यह एक विशेष इकाई या बैंक हो सकता है जिसे चलनिधि की आवश्यकता हो, जबकि पूरी प्रणाली अधिशेष में हो। निश्चित रूप से, हम चाहेंगे कि बैंक आपस में उधार लें और दें ताकि हमें वीआरआर न करना पड़े, और मुझे लगता है कि मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी इसका उल्लेख किया था। लेकिन फिर भी, कुछ बैंक रिजर्व बैंक के पास आना पसंद करते हैं, इसलिए हम उनके लिए उस अवसर को समाप्त नहीं करना चाहते। इसलिए वह मौजूद है। दूसरा प्रश्न यह है कि आगे चलकर विनिमय दर क्या होगी और चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हमारा मानना है कि यह हमारी आधारभूत धारणा है, और हमने कहा है कि दोनों तरफ जोखिम हैं और आपने इसे देखा भी है। पिछले तीन-चार महीनों में भी, रुपये का मूल्य कभी एक छोर पर गया और कभी दूसरे छोर पर।

आप वास्तव में नहीं जान सकते कि अनिश्चितता कैसे है, इसलिए आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि निकट या मध्यम अवधि में क्या होने वाला है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगले, हमारे पास फाइनेंशियल एक्सप्रेस से श्री सचिन कुमार होंगे।

सचिन कुमार, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस:

शुभ अपराह्न, गवर्नर महोदय। मेरा प्रश्न भी उसी तरह का था।

संजय मल्होत्रा:

यह भावनाओं पर निर्भर करता है। चीजें रातों-रात बदल रही हैं, हर दिन एक नया दिन होता है।

सचिन कुमार, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस:

तो सर, मेरा प्रश्न यह है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में गंभीर चलनिधि की कमी के बावजूद, हमने देखा कि बैंकों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये स्थायी जमा सुविधा में जमा किए। और यह उस स्थिति में हुआ जब आपने पिछली बार उल्लेख किया था कि बैंकों को आपस में सक्रिय रूप से कारोबार करना चाहिए। तो, क्या आपका मानना है कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

संजय मल्होत्रा:

मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बाजार अपने आप काम करेंगे। हमें बाजारों को अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक की ओर से इस हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। और यह एक बहुत छोटा हिस्सा है। यह बहुत अधिक नहीं है। कल वीआरआर लगभग 23,000 करोड़ रुपये था, जबकि हमारे पास लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये का अधिशेष था। यह नगण्य नहीं है, लेकिन यह बहुत अधिक भी नहीं है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अंत में, दूरदर्शन से श्रीमती श्यामा, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:

नमस्कार सर। हाल ही में एक बड़े शहरी सहकारी बैंक एक घटना घटित हुई, उसके बाद आपने के साथ बैठक की। तो आप सहकारी क्षेत्र के बैंकों की सेहत के बारे में क्या कहेंगे और आप सामान्य ग्राहकों को कैसे आश्वस्त करेंगे?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास एक संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र है, और जब मैं बैंकिंग क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो उसके अंतर्गत हमारे शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र भी आते हैं। कुल मिलाकर, बैंकिंग क्षेत्र के वित्त बहुत अच्छे हैं और वे काफी मजबूत हैं। और यदि आप शहरी सहकारी बैंकों की बात करें, तो उनका पूंजी जोखिम भारित अनुपात (सीआरएआर) भी बहुत मजबूत है, यह 15% से ऊपर है। साथ ही, आप देखते हैं कि वे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में, वे लोगों से लगभग 5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ रुपये के जमा राशि ले रहे हैं, और यह लगातार बढ़ रही है। यह ऐसा नहीं है कि यह सिकुड़ रही हो। कोई भी क्षेत्र जो पिछले 20 वर्षों से बढ़ रहा है, एक प्रणाली के रूप में, यह अपनी ताकत और महत्व को दर्शाता है। जैसा कि मैंने कहा है, कभी-कभी यह एक बैंक, एनबीएफसी या शहरी सहकारी बैंक हो सकता है जहां इस प्रकार की घटनाएं कभी-कभार उत्पन्न हो सकती हैं, और जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी, हम तदनुसार करेंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। इसके साथ ही हम इस प्रेस कान्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। प्रश्नों को स्वीकार करने के लिए मैं गवर्नर महोदय और उप गवर्नर महोदयों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद और मैं आप सभी के लिए सुखद दिन की कामना करता हूं।